Directive Principles Of State Policy (DPSP)

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

- The Directive Principles of State Policy are enumerated in Part IV of the Indian Constitution from Articles 36 to 51./ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 36 से 51 तक सूचीबद्ध किया गया है।
- The idea of DPSP is borrowed from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution./ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार 1937 के आइरिस संविधान से लिया गया है, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था।
- Dr. BR Ambedkar described these principles as ‘novel features’ of the Indian Constitution./ डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की 'नवीन विशेषताएँ' बताया।
- Granville Austin described the DPSP and Fundamental rights as the ‘conscience of the constitution.’/ ग्रानविले ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को 'संविधान की अंतरात्मा' बताया।
- Mentioned in the Government of India Act, 1935 as 'Instrument of Instructions’. / भारत सरकार अधिनियम, 1935 में 'निर्देशों के साधन' के रूप में उल्लेख किया गया है।

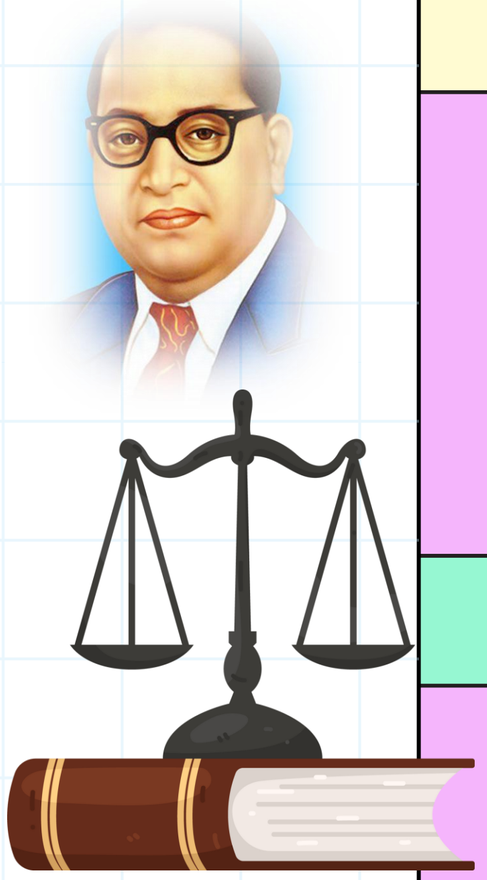

Features of DPSP :

- DPSPs are guidelines or principles given to the State to frame laws and policies./ नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को कानून और नीतियाँ बनाने के लिए दिए गए दिशानिर्देश या सिद्धांत हैं।
- Aim to establish social and economic democracy./ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य।
- Non-justiciable but fundamental in governance/ न्यायोचित नहीं, लेकिन शासन में मौलिक
- The directive Principles though non-justiciable in nature, but help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law./ निदेशक सिद्धांत यद्यपि न्यायोचित नहीं हैं, लेकिन ये न्यायालयों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जाँच और निर्धारण में सहायता करते हैं।

Objectives of DPSP :

- **To ensure social, economic, and political justice.**
  सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना।
- **To reduce inequality of income, status, and opportunities.**
  आय, स्थिति और अवसरों की असमानता को कम करना।
- **To promote welfare of the people.**
  जन कल्याण को बढ़ावा देना।
- **To provide the foundation for economic democracy.**
  आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखना।

Classification of DPSP :

Socialistic Principles / समाजवादी सिद्धांत:

- These principles reflect the ideology of socialism. / ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को प्रतिबिम्बित करते हैं।
- They lay down the framework of a democratic socialist state, aim at providing social and economic justice./ ये एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है।

Articles : 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47

Gandhian Principles / गांधीवादी सिद्धांत:

- These principles are based on Gandhian ideology / ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं।
- They represent the program of reconstruction enunciated by Gandhi during national movement./ ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Articles : 40, 43, 43B, 46, 47, 48

Liberal- Intellectual Principles / उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत:

- These are inspired by liberal democracies of the West and aim to establish political and international justice./ ये पश्चिमी उदार लोकतंत्रों से प्रेरित हैं और इनका उद्देश्य राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय न्याय स्थापित करना है।

Articles : 44, 45, 48A, 49, 50, 51

Important Amendments in Directive Principles :

The 42nd Amendment Act of 1976 added four new Directive Principles to the Original list./ 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने मूल सूची में चार नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े।

- To secure opportunities for healthy development of children [Article 39(f)]./ बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित करना [अनुच्छेद 39(f)]।
- To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor [Article 39(A)]/ समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना [अनुच्छेद 39(ए)]।
- To take steps to secure the participation of workers in the management of industries [Article 43(A)]./ उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना [अनुच्छेद 43(ए)]।
- To protect and improve the environment and to safeguard forests and wild life [Article 48(A)]./ पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करना [अनुच्छेद 48(ए)]।

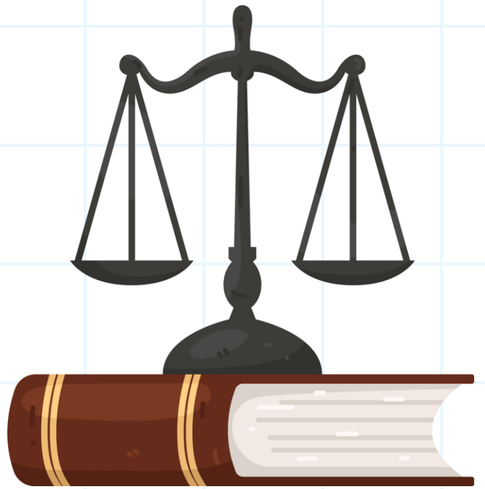

The 44th Amendment Act of 1978 added one more directive principle i.e. the state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities (Article 38) / 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने एक और नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा, अर्थात् राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करेगा (अनुच्छेद 38)।

The 86th Amendment Act of 2002 changed the subject – matter of Article 45 and made elementary education a fundamental right under Article 21A./ 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 के विषय-वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बना दिया।

The 97th Amendment Act of 2011 added a new directive principle relating to co-operative societies.[Article 43(B)] / 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा [अनुच्छेद 43(B)]।

Difference Between Fundamental Rights and DPSP

Fundamental Rights	Directive Principles
1. These are negative as they prohibit the state from doing certain things	1. These are positive as they require the state to do certain things.
2. These are justiciable in nature	2. These are non-justiciable in nature
3. They aim at establishing political democracy in the country	3. They aim at establishing social and economic democracy in the country
4. They promote the welfare of the individual	4. They promote the welfare of the community. They are societarian and socialistic.
5. They do not require any legislation for their implementation	5. They require legislation for their implementation.
6. The courts are bound to declare a law violative of any of the fundamental Rights as unconstitutional and invalid	6. The courts cannot declare a law violative of any of the directive Principles as unconstitutional and invalid.
7. They have legal sanctions	7. The have moral and political sanctions.

मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच अंतर

मौलिक अधिकार	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
1. ये नकारात्मक होते हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं।	1. ये सकारात्मक होते हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ कार्य करने हेतु निर्देश देते हैं।
2. इनका स्वरूप न्यायालय में लागू करने योग्य (न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय) होता है।	2. इनका स्वरूप न्यायालय में लागू न करने योग्य (अप्रवर्तनीय) होता है।
3. इनका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।	3. इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
4. ये व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं।	4. ये समाज के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये समाजवादी और सामुदायिक प्रकृति के होते हैं।
5. इनके कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती।	5. इनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है।
6. न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकते हैं।	6. न्यायालय नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले किसी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकते।
7. इन्हें कानूनी प्रतिबंध का समर्थन प्राप्त है।	7. इन्हें नैतिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त है।

Landmark Cases

- **Champakam Dorairajan (1951) – FRs prevail over DPSPs**
- **चंपकम दोराईराजन (1951) - एफआर, डीपीएसपी पर हावी हैं**
- **Kesavananda Bharati (1973) – Harmony is basic structure/ केशवानंद भारती (1973) - सामंजस्य बुनियादी संरचना है**
- **Minerva Mills (1980) – Balance is essential between FRs & DPSPs/ मिनर्वा मिल्स (1980) - एफआर और डीपीएसपी के बीच संतुलन आवश्यक है**

Criticism of the Directive Principles

No legal force/ कोई कानूनी बल नहीं:

- The directive principles have been criticized mainly because of their non-justiciable nature./ निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना मुख्यतः उनके गैर-न्यायसंगत स्वभाव के कारण की गई है।
- KC Wheare called them as ‘manifesto of aims and aspirations’./ के.सी. व्हेयर ने इन्हें 'उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणापत्र' कहा है।
- T.T. Krishnamachari describes the directives as ‘a veritable dustbin of sentiments’/ टी.टी. कृष्णमाचारी ने निर्देशों को 'भावनाओं का वास्तविक कूड़ेदान' बताया है।
- K.T Shah called them with ‘a cheque on a bank, payable only when the resources of the bank permit’./ के.टी. शाह ने इन्हें 'बैंक पर एक चेक के समान बताया है, जिसका भुगतान तभी किया जा सकता है जब बैंक के संसाधन अनुमति दें।'

टी.टी. कृष्णमाचारी

के.टी. शाह

Illogically arranged / अतार्किक रूप से व्यवस्थित:

- According to N. Srinivasan, 'the directives are neither properly classified nor logically arranged./ एन. श्रीनिवासन के अनुसार, 'निर्देशिकाएँ न तो उचित रूप से वर्गीकृत हैं और न ही तार्किक रूप से व्यवस्थित हैं।'
- The declaration mixes up relatively unimportant issues with the most vital economic and social question./ यह घोषणापत्र अपेक्षाकृत महत्वहीन मुद्दों को सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों के साथ मिला देता है।

Constitutional conflicts / संवैधानिक संघर्ष:

- K Santhanam has pointed out that the Directives lead to a constitutional conflicts/ के. संथानम ने बताया है कि ये निर्देशिकाएँ संवैधानिक संघर्षों को जन्म देती हैं।
- Between the centre and the states/ केंद्र और राज्यों के बीच
- Between the President and the Prime Minister/ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच
- Between the governor and the chief minister./ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच।

Conservative in nature/ रूढ़िवादी प्रकृति:

- According to Sir Ivor Jennings, the directives are based on the political philosophy of the 19th century England./ सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार, ये निर्देशिकाएँ 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं।
- Part IV of the constitution expresses 'Fabian Socialism without the socialism'./ संविधान का भाग IV 'समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद' को व्यक्त करता है।

Implementation of DPSPs

Since the 1950, the successive governments at the Centre and in the states have made several laws and formulated various programmes for implementing the Directive Principles. These are mentioned below:/ 1950 के बाद से, केंद्र और राज्य सरकारों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए कई कानून बनाए हैं और विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए हैं। इनका उल्लेख नीचे किया गया है:

• The planning commission / योजना आयोग	Established in 1950, aimed at securing socio-economic justice and reducing inequalities of income, status and opportunities./ 1950 में स्थापित इस संगठन का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना तथा आय, स्थिति और अवसरों की असमानताओं को कम करना है।
• Abolition of Zamindari system/ जमींदारी प्रथा का उन्मूलन	To ensure equitable distribution of land / भूमि का समान वितरण सुनिश्चित करना
• Minimum wages Act, 1948/ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	To secure fair wages for workers/ श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित करना
• Maternity Benefit Act, 1961/ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961	For protection of women and children/ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए
• Panchayati Raj System / पंचायती राज व्यवस्था	To promote village self-government (Article 40)/ ग्राम स्वशासन को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 40)
• Nationalization of banks and industries/ बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	To reduce economic inequalities/ आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए
• Right to education Act, 2009/ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	To ensure free and compulsory education (Article 45)/ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 45)
• MGNREGA	Right to work (Article 41)/ काम करने का अधिकार (अनुच्छेद 41)
• Environment Protection Act / पर्यावरण संरक्षण अधिनियम	Article 48A

Important Articles Related to directive Principles of State Policy

Article No./ अनुच्छेद सं.	Subject Matter / विषय वस्तु	Nature/category / प्रकृति / श्रेणी
Article 36	Definition of State / राज्य की परिभाषा	
Article 37	Application of the DPSPs (non-justiciable but fundamental in governance) / राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग (अप्रतिवादी लेकिन शासन में मूलभूत)	
Article 38	Promotion of welfare of people and reduction of inequalities / जनकल्याण को बढ़ावा और असमानताओं में कमी	**socialist / समाजवादी**
Article 39	Principles of policy - right to livelihood, equal pay, prevention of wealth concentration / नीतियों के सिद्धांत – आजीविका का अधिकार, समान कार्य का समान वेतन, संपत्ति के संकेंद्रण की रोकथाम	**socialist / समाजवादी**
Article 39A	Equal justice and free legal aid / समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता	**socialist / समाजवादी**
Article 40	Organisation of Panchayati Raj / पंचायत राज की संरचना	**Gandhian / गाँधीवादी**

Article No./ अनुच्छेद सं.	Subject Matter / विषय वस्तु	Nature/category / प्रकृति / श्रेणी
Article 41	Right to work, education, and public assistance / काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार	**socialist / समाजवादी**
Article 42	Humane conditions of work and maternity relief / मानवीय कार्य परिस्थितियाँ और मातृत्व सहायता	**socialist / समाजवादी**
Article 43	Living wage for workers and promotion of cottage industries / श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा	**Socialist & Gandhian / समाजवादी एवं गाँधीवादी**
Article 43A	Workers' participation in management of industries / उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी	**socialist / समाजवादी**
Article 43B	Promote cooperatives / सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा	**Gandhian / गाँधीवादी**
Article 44	Uniform civil code for all citizens / सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता	**Liberal- intellectual / उदारवादी–बौद्धिक**
Article 45	Early childhood care and education (below 6 years) / प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (6 वर्ष से कम आयु)	**Liberal- Intellectual / उदारवादी–बौद्धिक**

Article No./ अनुच्छेद सं.	Subject Matter / विषय वस्तु	Nature/category / प्रकृति / श्रेणी
Article 46	Promotion of educational and economic interests of SCs, STs and weaker sections / अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा	**Gandhian / गाँधीवादी**
Article 47	Raise level of nutrition, standard of living, and public health; prohibit intoxicant / पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाना; नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना	**socialist & Gandhian / समाजवादी & गाँधीवादी**
Article 48	Organisation of agriculture and animal husbandry; prohibition of cow slaughter / कृषि और पशुपालन का संगठन; गौ-हत्या पर प्रतिबंध	**Gandhian / गाँधीवादी**
Article 48A	Protection and improvement of environment and forests / पर्यावरण और वनों की रक्षा एवं सुधार	**Liberal- intellectual / उदारवादी–बौद्धिक**
Article 49	Protection of monuments and national heritage / स्मारकों और राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण	**Liberal- Intellectual / उदारवादी–बौद्धिक**
Article 50	Separation of judiciary from executive / न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना	**Liberal- intellectual / उदारवादी–बौद्धिक**
Article 51	Promotion of international peace and security / अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना	**Liberal- Intellectual / उदारवादी–बौद्धिक**

QUESTION

Q1. Which part of the Constitution of India describes the model of welfare state?

भारतीय संविधान का कौन-सा भाग कल्याणकारी राज्य के मॉडल का वर्णन करता है?

a) Fundamental Rights / मौलिक अधिकार

b) Fundamental Duties / मौलिक कर्तव्य

c) The Preamble / प्रस्तावना

d) Directive Principles of State Policy / राज्य के नीति निदेशक तत्व

IAS Pre 2020, SSC CGL T-2 02/03/2023

Question

Q2. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates _

भारतीय संविधान के अनुसार, धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है?

a) The Right to Equality / समानता का अधिकार

b) The DPSPs / राज्य के नीति निदेशक तत्व

c) The Right to Freedom / स्वतंत्रता का अधिकार

d) The concept of welfare / कल्याण की अवधारणा

IAS Pre 2021

Question

Q3. Which article of the Indian Constitution says that DPSPs are not enforceable by any court?

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं?

a) Article 39 / अनुच्छेद 39

b) Article 38 / अनुच्छेद 38

c) Article 36 / अनुच्छेद 36

d) Article 37 / अनुच्छेद 37

Jharkhand PCS 2023

QUESTION

Q4. Identify the correct pair mentioning the Directive Principles of State Policy in the Constitution of India.

भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित सही जोड़ी की पहचान करें।

a) Equal justice and free legal aid – Article 42 / समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता – अनुच्छेद 42

b) Organisation of agriculture and animal husbandry – Article 43 / कृषि एवं पशुपालन का संगठन – अनुच्छेद 43

c) Organisation of village panchayat – Article 41 / ग्राम पंचायतों का संगठन – अनुच्छेद 41

d) Equal pay for equal work for both men and women – Article 39 / पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन – अनुच्छेद 39

RAS Pre 2021

QUESTION

Q5. MGNREGA scheme has been launched as a part of implementing which one of the following Articles of the Indian Constitution?

मनरेगा योजना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन का हिस्सा है?

a) Article 43 / अनुच्छेद 43

b) Article 45 / अनुच्छेद 45

c) Article 47 / अनुच्छेद 47

d) Article 50 / अनुच्छेद 50

UP UDA

Question

Q6. Which of the following Articles of the Constitution of India talks about the Uniform Civil Code (UCC)?

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित है?

a) Article 43 / अनुच्छेद 43

b) Article 44 / अनुच्छेद 44

c) Article 45 / अनुच्छेद 45

d) Article 46 / अनुच्छेद 46

Jharkhand PCS 2023

Question

Q7. POSHAN Abhiyan is a programme to improve the nutritional status of children from 0 to 6 years. Which of the following Articles of the Indian Constitution provides for raising the nutrition level?

पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की पोषण स्थिति सुधारने के लिए एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद पोषण स्तर बढ़ाने का प्रावधान करता है?

a) Article 47 / अनुच्छेद 47

b) Article 44 / अनुच्छेद 44

c) Article 46 / अनुच्छेद 46

d) Article 45 / अनुच्छेद 45

SSC CHSL 14/08/2023

QUESTION

Q8. The State shall endeavour to secure to all workers ‘a living wage and a decent standard of life’. Which of the following is correct regarding the statement in the context of India?

राज्य सभी श्रमिकों के लिए 'जीवन निर्वाह योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर' सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा सही है?

a) It is mentioned in the 43rd Article of the Constitution / यह संविधान के अनुच्छेद 43 में उल्लेखित है

b) It is mentioned in the 44th Article of Constitution / यह संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है

c) This is a Gandhian principle of DPSP / यह DPSP का गाँधीवादी सिद्धांत है

d) This is a liberal principle of DPSP / यह DPSP का उदारवादी सिद्धांत है

SSC CHSL 10/08/2023

QUESTION

Q9. Which part of the Indian Constitution deals with the Directive Principles of State Policy?

भारतीय संविधान का कौन-सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है?

a) Part III / भाग III

b) Part II / भाग II

c) Part IV / भाग IV

d) Part I / भाग I

SSC GD 2024

Question

Q10. In which year were four new Directive Principles added to the original list?

मूल सूची में चार नए राज्य के नीति निदेशक तत्व किस वर्ष जोड़े गए थे?

a) 1977

b) 1975

c) 1976

d) 1980

SSC CPO 27/06/2024

Question

Q11. Consider the following pairs: / निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

Provisions in the Constitution / संविधान में प्रावधान	Stated under / उल्लेखित
(a) Separation of judiciary from the executive in the public services of the state / राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना	The Directive Principles of State Policy / राज्य के नीति निदेशक तत्व
(b) Valuing and preserving the rich heritage of our composite culture / हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत का मूल्यांकन और संरक्षण	The Fundamental Duties / मौलिक कर्तव्य
(c) Prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories / 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम पर लगाने पर प्रतिबंध	The Fundamental Rights / मौलिक अधिकार

How many of the above pairs are correctly matched?

उपरोक्त में से कितने युग्म सही मेल खाते हैं?

a) Only one / केवल एक
b) Only two / केवल दो
c) All three / सभी तीन
d) None / कोई नहीं

UPSC Pre 2025

QUESTION

Q12. Which of the following statements are correct about Directive Principles of State Policy of the Indian Constitution?

भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

a) They are negative in nature / ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं

b) They have moral and political sanctions / इनमें नैतिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है

c) They promote the welfare of the rich / ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं

d) They are positive in nature / ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं

SSC CHSL 10/08/2023

QUESTION

Q13. Which of the following Articles of the Indian Constitution provides that the State must secure a social order for the promotion of the welfare of the people?

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य को जनकल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए?

a) Article 37 / अनुच्छेद 37

b) Article 38 / अनुच्छेद 38

c) Article 39 / अनुच्छेद 39

d) Article 36 / अनुच्छेद 36

SSC CGL 12/09/2024

Question

Q14. Which article of the Indian Constitution mentions that 'The State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas'?

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि 'राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा'?

a) Article 44 / अनुच्छेद 44

b) Article 49 / अनुच्छेद 49

c) Article 43 / अनुच्छेद 43

d) Article 42 / अनुच्छेद 42

SSC CGL 19/09/2024

Question

Q15. Which of the following provisions is a part of both Directive Principles of State Policy and Fundamental Duties?

निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का हिस्सा है?

a) Participation of workers in management of industries / उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

b) Protection of environment / पर्यावरण का संरक्षण

c) Guardians to provide opportunity for education to children / बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना

d) Uniform Civil Code / समान नागरिक संहिता

UPPCS Pre 2023

QUESTION

Q16. “The Directive Principles of State Policy is a cheque which is paid on Bank’s convenience,” who said it?

“राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार भुनाया जाता है,” यह किसने कहा था?

a) B. R. Ambedkar / बी. आर. आंबेडकर

b) K. M. Munshi / के. एम. मुंशी

c) Dr. Rajendra Prasad / डॉ. राजेंद्र प्रसाद

d) K. T. Shah / के. टी. शाह

UPPCS Pre 2007

QUESTION

Q17. Who among the following considered the Directive Principles of State Policy as aiming at "furthering the goals of social revolution"?

निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को "सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने" वाला माना था?

a) B. N. Rau / बी. एन. राव

b) Granville Austin / ग्रैनविल ऑस्टिन

c) K. C. Wheare / के. सी. व्हीयर

d) Rajni Kothari / रजनी कोठारी

CDS 2021

Question

Q18. Which Article of the Indian Constitution mandates that the State should protect every monument or place of artistic or historic interest?

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह अनिवार्य करता है कि राज्य प्रत्येक कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारक या स्थान की रक्षा करे?

a) Article 39A / अनुच्छेद 39A

b) Article 50 / अनुच्छेद 50

c) Article 49 / अनुच्छेद 49

d) Article 48A / अनुच्छेद 48A

Question

Q19. Which of the following Articles from Directive Principles of State Policy mentions about the organization of Village Panchayats?

राज्य के नीति निदेशक तत्वों के निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख करता है?

a) Article 38 / अनुच्छेद 38

b) Article 42 / अनुच्छेद 42

c) Article 40 / अनुच्छेद 40

d) Article 36 / अनुच्छेद 36

SSC CGL 17/09/2024

ANSWER KEY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D	B	D	D	A	B	A	A	C	C	C	D	B	C	B	D	B	C	C

THANK YOU